THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI p. K. THUNGON): (a) It is estimated that about 488 lakh people were living in slums and squatter Settlements in the country in 1990.

(b) Based on 1971 and 1981 census data the National Building Organisation has estimated the housing shortage be of the order of 33 million units on the 1st March, 1993. The housing shortage in India by the turn of the country, i.e. on the 1st March, 2001, is estimated to be 41 million units.

(c) Housing being a State subject, it is primarily the responsibility of State Governments to take steps to remedy the situation of housing shortage.

The National Housing Policy lays down various steps which would be needed to be taken by at Central, State and Municipal level to accelerate the pace of house construction. These include:—

(i) removal of legal and other constraints;

(ii) increasing the inflow of housing finance;

(iii) stepping up the supply of developed land, infrastructural service, cost effective technology and building materials, etc.; and

(iv) formulation and implementation of timey bound Action Plains by State Governments with the guidance of Central Government.

संपदा निदेशालय के अधिकारियों तथा प्रोपर्टी डीलरों के बीच मिलीभगत होना

3453. श्री राम सिंह राठवा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सम्पदा निदेशालय के अधिकारियों तथा प्रोपर्टी डीलरों के बीच मिलीभगत है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में अपने स्तर पर जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्लर्क यूनियन से एक शिकायत मिली थी, जिसमें प्रापर्टी डीलरों द्वारा सम्पदा निदेशालय के कर्मचारियों की मिलीभगत से सम्पदा निदेशालय के परिसरों का उपयोग करके कथित अवांछित गतिविधियों का जिक्र था।

(ख) से (ङ) शिकायत में उल्लिखित अवांछित गतिविधियों से संबंधित सूचना नितान्त सामान्य प्रकार की थी अतः कोई जांच सम्भव नहीं थी, फिर भी परिसरों के दुरुपयोग/उपकिरायेदारी की निदेशालय द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है और दोषी कर्मचारियों को नियमों के अनुसार दण्डित किया जाता है।

Illegal encroachment at Manakapura

3454. SHRI A. NALLASIVAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been illegal encroachment on public land at Manakpura; and

(b) if so, the details thereof and what steps have been taken by Government in this regard?